

सूरत में बच्ची को पीटने वाले शिक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश

टीचर की गलती का एहसास होते ही स्कूल प्रबंधकों ने तुरंत टीचर को त्यागपत्र लिख दिया

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत : हाल ही में शहर के कापोद्रा इलाके में स्थित साधना स्कूल में एक शिक्षक ने एक छोटी बच्ची की बेरहमी से पीटाई की। जूनियर केजी छात्रा जब लड़की घर गई तो कपड़े बदलते समय उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर उसकी मां ने स्कूल में शिकायत की। साधना निकेतन स्कूल उस वक्त सीसीटीवी में देखा गया कि टीचर लड़की को पीट रहा था। शिक्षक गिरफ्तार दूसरी ओर, लड़की के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जिसके चलते आज शिक्षक



को गिरफ्तार कर लिया गया है और शिक्षा अधिकारी के आदेश पर स्कूल द्वारा शिक्षक का इस्तीफा भी ले लिया गया है। पुलिस मामला कापोद्रा पुलिस ने महिला शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और शिक्षा मंत्री ने आगे की जांच के आदेश दिए हैं।

से नहीं लिखने से गुस्साई शिक्षिका जशोदाबेन ने बच्ची को पीट और गाल पर मारा। जब लड़की घर पहुंची और अपनी वर्दी बदल रही थी, तो उसकी पीठ पर कुछ लाल निशान दिखाई दिए। तो बच्ची की मां ने बताया कि बच्ची से इस बारे में पूछने पर टीचर ने उसकी पीटाई की। शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पंसेरिया ने जांच के आदेश दिये हैं

शिक्षिका जशोदा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया बच्ची की मां तुरंत स्कूल पहुंची और शिक्षकों को मामले की जानकारी दी। इसके बाद जब स्कूल ने सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो पता चला कि बच्ची को टीचर ने

बिना टेंडर प्रक्रिया पूरी किए 80 करोड़ का काम दे दिया

बाकी कंपनियों कम कीमत पर काम करने के इंतजार में रह गईं

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत नगर निगम में सत्तास्व भारतीय जनता पार्टी ने कंप्यूटर ऑपरेटर आपूर्ति कंपनियों आकार और सुकानी

भारी वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए तीन और वर्षों के लिए प्रति माह 19,300 ऑपरेटरों को काम सौंपा। जो दरअसल नियम विरुद्ध बताया जा रहा है। हालांकि यह बात काफी समय से पता थी कि तीन साल खत्म होने वाले हैं, निगम को कम कीमत पर कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, अगर वास्तव में निविदा जारी की गई थी। पायल सकारिया ने कहा कि सूरत नगर निगम सालाना करोड़ों रूप का मुनाफा कमा



को 2020 के भीतर एक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नगर पालिका में विभिन्न पदों पर ऑपरेटरों की आपूर्ति करने के लिए एक साल और दो साल के लिए 10% की वार्षिक वृद्धि के साथ सम्मानित किया, लेकिन ये तीन साल पूरे होने के बाद नई टेंडरिंग प्रक्रिया करने की बजाय आज दोनों कंपनियों को दोबारा काम सौंपा गया, इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थायी समिति ने

लेकिन इसके लिए टेंडर जारी नहीं किया गया। कंप्यूटर ऑपरेटर समेत मेन पावर सप्लाय करने वाली एक अन्य कंपनी ने आयुक्त को पत्र लिखकर सूरत नगर आयुक्त को पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि इन सभी के अधीन एक ही काम होगा। शर्तें, हम 16 रुपये का भुगतान करेंगे। हम इसे हजार की कीमत पर करने के लिए तैयार हैं। यह पाया गया है कि अधिक एजेंसियां सूरत नगर

सकता था, लेकिन व्यापक भ्रष्टाचार के कारण स्थायी समिति ने उम्र जाकर पहले ही काम सौंप दिया और सूरत 80 करोड़ रुपये के अनुमानित नुकसान का जिम्मेदार नगर निगम बना आयुक्त को इस प्रस्ताव को तुरंत रद्द करने और नए सिरे से निविदा प्रक्रिया आयोजित करने की आवश्यकता है। हम फोटो निर्णयों के कारण नगर निगम के खजाने की खुली लूट का विरोध करते हैं।

स्पा और मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे गोरखधंधों का भंडाफोड़ अब सूरत पुलिस आयुक्त के सामने नई चुनौती

इच्छानाथ में किराए के फ्लैट से पकड़े गए तस्करो के बाद, घोड्डो रोड, खरवासा रोड के फ्लैटों से दो और पकड़े गए

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के विभिन्न इलाकों में स्पा और मसाज पार्लरों की आड़ में कमिश्नर के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। सूरत पुलिस की स्पा के खिलाफ कार्रवाई के बाद शहर के कोने वाले फ्लैटों में एक बार फिर बदमाश सक्रिय हो गए हैं। किराए के फ्लैट से बदमाश पकड़े जाने के बाद सूरत के

इच्छानाथ में घोड्डो रोड, खरवासा रोड फ्लैट्स से दो और बदमाश पकड़े गए।

सूरत क्राइम ब्रांच की IU-CAW सेल ने उमरा पुलिस सीमा में इच्छानाथ नेहरूगर के पीछे शिवम अपार्टमेंट के एक किराए के फ्लैट में चल रहे वेश्यालय का भंडाफोड़ किया और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, शिमला से चार लालन को मुक्त करवाया। फ्लैट के किराएदार को वांछित घोषित किया गया और आगे की कार्रवाई

की गई। लिया गया। उसके बाद, कल, अपराध शाखा की मानव तस्करी विरोधी इकाई ने प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया और एक लालाना को मुक्त करवा दिया, जो घोड्डो रोड के पास राज घर ज्वैलर्स के पीछे धनराज अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर एक किराए के फ्लैट में पाया गया था। उमरा पुलिस स्टेशन। वेश्यालय के मूल मालिक और एजेंट को वांछित घोषित किया गया था। मानव तस्करी विरोधी इकाई ने ही डिंडोली

पुलिस स्टेशन में खरवासा रोड मार्क प्वाइंट कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर एक फ्लैट में महिला संचालिका और ग्राहक को गिरफ्तार किया और मुक्त करवाया। दो लालन। लंबे समय से सूरत के विभिन्न इलाकों में स्पा और मसाज पार्लर की आड़ में कुतनखाने चल रहे थे। अब भी कई जगहों पर ये चल रहे हैं लेकिन सूरत पुलिस की कार्रवाई के कारण इनकी संख्या पहले की तुलना में कम हो गई है। करवा

सिटी ने चार महिला पुलिस अधिकारियों को मैदान में उतारा और पुलिस को इसमें सफलता भी मिली, लेकिन कुतनखाना संचालकों ने पुलिस से बचने के लिए अपना पुराना तरीका फिर से शुरू कर दिया है। सूरत के कुछ रिहायशी इलाकों में फ्लैट या मकान किराए पर लिए जाते थे स्पा और मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे गोरखधंधे को रोकने वाले पुलिस कमिश्नर के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है।

सूरत के पांच तालुकाओं की 1300 सरकारी भूमि संख्या की ई-मैपिंग के लिए सर्वेक्षण शुरू

राज्य में सबसे पहले सूरत में सर्वे शुरू हुआ

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीन के साथ-साथ भविष्य में भी जमीन की भारी कमी है। सूरत जिला कलेक्टर ने मुकदमेबाजी या दबाव से बचने के लिए गुजरात में पहली बार सूरत शहर के पांच तालुकाओं के 1300 सर्वेक्षण संख्याओं में स्थित सरकारी भूमि की ई-मैपिंग शुरू की है। इस सर्वे नंबर का अक्षांश-देशांतर, फोटो सहित ब्योर ऑनलाइन अपलोड करने पर यह सीधे गूगल मैप में खुल जाएगा। सूरत शहर के पांच तालुका उधना, माजुया, कतारामा, अडाजण और पुणे में विभिन्न सरकारी भूमि हैं। इन जमीनों के साथ-साथ जब नगर पालिका और टाउन प्लानिंग से प्लान पास होता है तो कुल जमीन का 40 फीसदी हिस्सा कटौती में चला जाता है। इन सभी जमीनों को मिलाकर

सूरत शहर के पांच तालुकाओं में लगभग 1300 सरकारी नंबर की जमीनें हैं। दूसरी ओर, सूरत के जिला कलेक्टर आयुष ओक ने इन सभी सरकारी नंबरों का फील्ड एरिया मेजर ऐप

अक्षांश-देशांतर का डाटा होगा अपलोड : भविष्य में सरकारी जमीन की जख्त पड़ी तो एक क्लिक में सारी जानकारी फोटो के साथ उपलब्ध होगी।



(ई-मैपिंग) शुरू किया है ताकि यह जांचा जा सके कि भविष्य में इन जमीनों पर कोई दबाव है या नहीं। जिसमें सभी पांच तालुकाओं के उप मामलतदार, सर्कल अधिकारी जगह पर जाएंगे और सरकारी जमीनों की तस्वीरें लेंगे। साथ ही वहां से

जमीन का अक्षांश और देशांतर भी लिया जाएगा। इस प्रकार गूगल मैप, क्षेत्रफल, भूमि डेटा को मिलाकर एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। और जब भी सरकारी जमीन की मांग की जाती है। फिर एक क्लिक पर फोटो समेत सारी जानकारी मिल जाएगी। इन जमीनों पर दबाव है या नहीं? उसका

जमीनें कहा-कहां स्थित हैं। इसे अक्षांश एवं देशांतर से तुरंत जाना जा सकता है। इस वजह से जब किसी जमीन का अंतिम प्लॉट निर्धारित करना होता है तो अगर उसे सरकारी जमीन से लिया जाता है तो यह समझ में आ जाता है कि यह जमीन सरकारी की है। इसलिए फाइनेल प्लॉट (एफपी) को लेकर अब तक जो असमंजस चल रहा था। वह भी असंभव हो जायेगा।

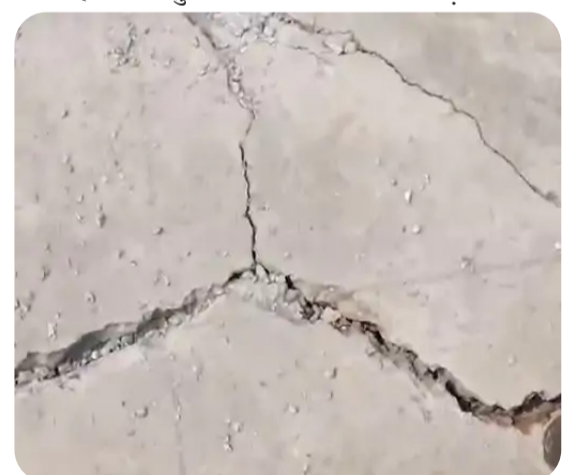
सूरत शहर की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है। और आने वाले वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि के साथ 2035 के विकास के लिए सरकारी भूमि की आवश्यकता भी उत्पन्न होगी। इसके चलते वर्तमान में जितनी जमीनें हैं। अगर इसकी ई-मैपिंग हो जाए तो भविष्य में जब भी निर्माण की जख्त होगी तो तुरंत पता चल जाएगा कि इस स्थान पर कितनी जमीन है। क्या यह सही है या नहीं?

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के अधिकारी केवल परियोजना को मंजूरी देने और इसे चालू करने में रुच रखते हैं, लेकिन यह देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि यह समय पर चालू हो रही है या नहीं। सूरत नगर निगम के शासकों और अधिकारियों की छवि यह है कि प्रोजेक्ट टेकेदार से जो भी लेन-देन होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। विपक्ष की ओर से भी समय-समय पर इस तरह के आरोप

सानिया हेमाड में तापी शक्ति परियोजना के तहत कार्यान्वित नहीं किया गया था, यह काम 2019 में हरित पर्यावरण को सौंपा गया था। 24 माह में काम शुरू करने का



लेकिन प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका. करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी हुक्मरान इस पर गंभीर क्यों नहीं हैं? यह समझ में नहीं आता. जनता के करोड़ों रुपये बर्बाद



लागे जाते रहते हैं. सूरत नगर निगम द्वारा 72 करोड़ रुपये की लागत से

निर्णय लिया गया था, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गयी कि जनता का पैसा खर्च हो गया,

अपने क्षेत्र में समस्याएं हमें लिखें या बताएं और समस्याएं का हल संबंधित विभाग से मिलेगा मोबाईल:-987914180 या फोटा, वीडियो हमें भेजे